सत्ता की चालों से सतर्क रहने का वक्त

जोगिन्दर सिंह उगराहा

आखिर वह दिन आ ही गया जिसके लिए लाखों किसान पिछले डेढ़ साल से धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष कर रहे थे। उनकी सबसे प्रमुख मांगों को स्वीकार करने की घोषणा खुद प्रधानमंत्री को करनी पड़ी। इस घोषणा को देश के किसानों और सभी मेहनतकश जनता ने अपनी सांस रोक कर उनके संघर्ष के प्रति सहानुभूति से सबसे अधिक ध्यान से सुना और लहरों की भावनाओं के बीच जीत और उत्सव के युद्ध के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। अपने प्राणों की आहुति देने वालों के चेहरे उनकी आंखों के सामने जिंदा दिखाई दिए। उनकी शहादत को याद किया गया और सम्मान दिया गया। देश के मेहनतकश जनसमुदाय ने अपनी एकता की गर्मजोशी, इस संघर्ष के शिखर का आनंद उठाया, जिसने कई उतार-चढ़ाव देखे।

लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा तीन कानूनों को निरस्त करने के निर्णय की घोषणा करने के लिए अपनाया गया तरीका भी उनके जनविरोधी फासीवादी मानसिक बनावट का एक और सबूत साबित हुआ है। उन्होंने न केवल मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने की आवश्यकता महसूस की बल्कि एकतरफा घोषणा का सहारा लेकर आंदोलन के नेतृत्व की उपेक्षा करने का प्रयास भी किया। सही रास्ता यह होता कि अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर किसान नेतृत्व के साथ बातचीत की जाती, जब इस विशाल जन आंदोलन की सबसे प्रमुख मांग को स्वीकार करने और आम सहमति तक पहुंचने का निर्णय लिया जाता। इन सभी प्रयासों को करने के बजाय, उन्होंने अपनी 'मोदी है तो मुमकिन है' की पहले से बनी छवि को सामने लाने की कोशिश की। यह एक ऐसी छवि है जो दूसरों की राय खो देती है, एक ऐसी छवि जिसके आधार पर मोदी ने हर तरह की असहमति की आवाज को दबा दिया है और लोगों की उचित और वास्तविक मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। यह बिल्कुल अलग बात है कि संघर्षशील लोगों के लिए इस उपलब्धि के मायने नहीं बदले जा सकते।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में तीन कानूनों के तहत काम कर रहे कृषि के कारपोरेटीकरण के जोर को जबरदस्ती जायज ठहराने की कोशिश की है। उन्होंने इन कानूनों के पीछे पूरे देश के किसानों की सार्वभौमिक सहमति और किसानों के व्यापक प्रतिरोध को एक छोटे से वर्ग की अप्रियता के रूप में दावा किया है। उन्होंने अपने संबोधन के माध्यम से, वास्तव में, वैश्विक साम्राज्यवादी कंपनियों और बड़े कॉरपोरेट्स से इन कानूनों पर लोगों को धोखा देने में सफल नहीं होने के लिए माफी मांगी है। साथ ही उन्होंने अपने पहले के पथ पर चलते रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। तथाकथित 'सुधारों' के हितों के लिए शून्य बजट खेती और फसल विविधीकरण जैसे विचारों को दोहराया गया है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद नरेंद्र तोमर ने अपने एक बयान में कृषि में 'सुधारों' को आगे बढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीके अपनाने की बात भी कही है।

इन सब से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कृषि क्षेत्र में कॉरपोरेट्स के प्रवेश के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता पहले की तरह है, और इसके लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोजने का प्रयास कर रही है। यहां तक कि एमएसपी के मुद्दे पर प्रस्तावित समिति भी इन रास्तों से बाहर नहीं है। जब कॉरपोरेट्स के हितों के प्रति प्रतिबद्धता इतनी प्रबल होती है, तो ये आसान जीत नहीं हो सकती है और पहले से हासिल की गई जीत के धुल जाने का खतरा हमेशा घूमता रहता है। तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के साथ ही हमारे खेतों और फसलों के लिए परेशानी कम नहीं हुई है। समय की बात है कि फिर से प्रयास किए जाएंगे। सरकारी खरीद से भागना आंदोलन के दौरान भी उसके एजेंडे में रहा है। कानूनों को निरस्त करने के समय, उस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी भाषा के गुप्त अर्थ को बारीकी से पढ़ने और पकड़ने की आवश्यकता होगी, ताकि किसानों के हितों को पीछे से मारने की साजिशों से अवगत हो सकें। सरकार की यह मंशा इस बात से स्पष्ट है कि सरकार अभी भी निजी मंडियों की स्थापना कर किसानों को 'आजादी' देने के अपने दावों से दूर नहीं हुई है।

अब भी सरकार की ओर से वर्तमान जीत को एक मानकीकृत और व्यापक जीत में बदलने से रोकने की कोशिश होगी, एक ऐसी जीत जो किसानों के हितों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। सरकार की मंशा अन्य मांगों को नज़रंदाज करने, एमएसपी और पीडीएस की कोई गारंटी या आश्वासन देने से बचने और किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं को कानूनी मामलों में उलझाए रखने की होगी।

इसलिए समय की मांग है कि सरकार की इन मंशाओं को सतर्क रहकर हरा दिया जाए और बची हुई मांगों को स्वीकार करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष जारी रखा जाए। जब तक संसद द्वारा तीन कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी और पीडीएस पर गारंटी और बिजली बिल, प्रदूषण बिल, मुकदमों की वापसी और मुआवजे से संबंधित अन्य मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक संघर्ष का झंडा ऊंचा रहना चाहिए। हमें उन कदमों पर सतर्क रहना चाहिए जो खरीद व्यवसाय में कॉरपोरेट्स के प्रवेश के लिए शुरू किए जा सकते हैं। ये प्रयास नए कानूनों के नाम पर या कार्यकारी आदेशों द्वारा या किसी अन्य गुप्त दरार के माध्यम से किए जा सकते हैं। तय है कि सरकार इस रास्ते से नहीं हटेगी। इसलिए लोगों को सतर्कता और एकता बनाए रखने के अलावा इन मुद्दों के प्रति जागरूक किया जाए। मांगों पर स्पष्टता के अभाव में सरकारें उन्हें उलझाने या रौंदने में सफल हो जाती हैं। कानूनों को निरस्त कर दिया गया है के उत्साही माहौल में, उनकी वास्तविक वापसी और अन्य मुद्दों के बारे में चिंताओं को नहीं भूलना चाहिए।

अब भी सरकार की ओर से वर्तमान जीत को एक मानकीकृत और व्यापक जीत में बदलने से रोकने की कोशिश होगी, एक ऐसी जीत जो किसानों के हितों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। सरकार की मंशा अन्य मांगों को नज़रंदाज करने, एमएसपी और पीडीएस की कोई गारंटी या आश्वासन देने से बचने और किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं को कानूनी मामलों में उलझाए रखने की होगी।

नि:संदेह इस संघर्ष का पहला चरण जीत लिया गया है। लेकिन मंडियों में फसलों को रौंदने से बचाने के लिए और पीडीएस के माध्यम से मेहनतकश जनता के लिए भोजन का अधिकार हासिल करने के लिए एक लंबे संघर्ष की आवश्यकता है। यह संघर्ष अब एक उच्च और दीर्घकालिक एकता की मांग करता है।

जरूरत इस बात की है कि संघर्ष के अंगारे को तब तक जलाए रखा जाए जब तक कि जीत की घोषणा हकीकत में तब्दील न हो जाए। वर्तमान समारोहों के बीच, बड़ी चिंताओं को नज़रंदाज़ नहीं करना चाहिए।

क्या अडानी को देने के लिए किया जा रहा है जेवर एयरपोर्ट का निर्माण ?

जेपी सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट की नींव रख दी है। केंद्र और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट 1,300 हेक्टेयर में फैला होगा। अभी भारत में सबसे बड़ा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा है। जेवर हवाईअड्डा दिल्ली-एनसीआर में बनने वाला दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। जेवर एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा, जिसमें मल्टी-मॉडल कार्गो हब की तरह बनाया गया है। यह भारत का पहला नेट-जीरो उत्सर्जन वाला एयरपोर्ट होगा। कहा जा रहा है कि यह 30 हजार करोड़ की लागत से बनेगा।लाख टके का सवाल है कि जब मोदी सरकार एक-एक करके देश के प्रमुख हवाई अड्डों को अडानी समूह को बेच रही है तो क्या जेवर हवाई अड्डा भी अडानी को देने के लिए टैक्स की कमाई से बनाया जा रहा है।

जेवर एयरपोर्ट पर शुरुआत में 2 रनवे बनाया जाएगा। लेकिन इसे बढ़ाकर 6 रनवे किया जाएगा, जो कि एक साथ ऑपरेट होगा। जब सभी 6 रनवे बनकर तैयार हो जाएंगे तो फिर जेवर एयरपोर्टह्ल भारत ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। यही नहीं, जेवर एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पर 3 रनवे हैं।

सरकार का लक्ष्य है कि साल 2024 से जेवर एयरपोर्ट शुरू हो जाए। यानी 36 महीने के बाद लोग जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भर सकेंगे। लेकिन इसके विस्तार पर काम आगे भी चलता रहेगा। इस एयरपोर्ट पर बनने वाले कार्गो टर्मिनल की क्षमता 20 लाख मीट्रिक टन होगी। इसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन तक किया जाएगा। जेवर का ये एयरपोर्ट एकदम हाईटेक होगा। हर सुविधा से लैस, विकास का सबसे बड़ा मॉडल। यहां एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे।

जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में 10,050 करोड़ रुपये की लागत आएगी। कहा जा रहा है कि इस एयरपोर्ट की वजह से करीब 35000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इस एयरपोर्ट के पहले चरण में सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की सेवा करने की क्षमता होगी। जबकि 2040-50 के बीच जेवर हवाईअड्डा सालाना 7 करोड़ यात्रियों को संभालेगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के बनने से 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जेवर एयरपोर्ट में सालाना करीब 7 करोड़ यात्रियों की क्षमता होगी। इसमें 186 एयरपोर्ट स्टैंड होंगे। जेवर एयरपोर्ट 51 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दबाव कम होगा।

इस बीच समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन पर सरकार पर निशाना साधते हुये कहा कि यह कैसी सरकार है जो एक तरफ तो हवाई अड्डे बेच रही है और दूसरी तरफ नया बना रही है। उन्होंने कहा कि यदि लोग अपना मन बना लें, तो 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जनता को इतनी दुख तकलीफ किसी सरकार ने नहीं दी होगी, जितनी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यहां सपा के सहयोगी दल जनवादी पार्टी सोशलिस्ट की जनक्रांति महारैली में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज शिलान्यास करने गये हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने कहा था कि हवाई चप्पल से चलने वाला हवाई जहाज से चलेगा। ऐसे कितने गरीब हैं जिन्होंने हवाई जहाज से यात्रा की है? देश में जितने भी हवाई अड्डे हैं सब घाटे में हैं। दिल्ली का हवाई अड्डा कई हजार करोड़ रूपये के घाटे में हैं।एयर इंडिया घाटे में है,बिक गया । निजी एयरलाइन भी घाटे में हैं।यह नया हवाई अड्डा इस लिये बन रहा है कि जब यह बनकर तैयार हो जायेगा भारतीय जनता पार्टी उसको भी बेच देगी।

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने कहा कि हवाई अड्डे की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन इस हवाई अड्डे के निर्माण पर 30,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस रकम से अगर हमारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए, तो इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और देश को ज्यादा लाभ होगा। कमलनाथ ने उत्तर प्रदेश के जेवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोएडा अंतरराष्ट्रीय विमान-तलकी नींव रखे जाने के औचित्य पर गुरुवार को सवाल उठाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सरकार के खजाने की हालत पर सवाल दागते हुए यह भी कहा कि सरकार जेवर में नया हवाई अड्डा बनाए, पर इसे बनाने की धन राशि कहां से आएगी?

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर इसकी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या-451102010004150
IFSC Code : UBIN0545112
Union Bank of India, Sector-7, Faridabad